2

परिषदीय विद्यालयों में निपुण भारत मिशन की कार्यान्वयन स्थिति एवं चुनौतियों का अध्ययन

कुंदन सिंह*
प्रतिभा सागर**
बिजेंद्र सिंह***

शिक्षा मनुष्य के जीवन को उन्नत करने हेतु एक सामाजिक प्रक्रिया है। किसी राष्ट्र की उन्नति को उसकी शैक्षिक उपलब्धियों से मापा जा सकता है। किसी राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति व समृद्धि के सुधार में शिक्षा एक प्रभावी भूमिका निभा सकती है। स्वतंत्रता पश्चात भारत में शैक्षिक सुधार हेतु अनेक योजनाएँ, आयोगों, शिक्षा नीतियों, समितियों व पाठ्यचर्याओं का गठन व निर्माण किया जा चुका है। शैक्षिक ढाँचे व परिवर्तित हो रहे वैश्विक शैक्षिक परिदृश्य के क्रम में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के आलोक में निपुण (NIPUN— National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding & Numeracy) भारत मिशन का आरंभ 5 जुलाई 2021 को किया गया। निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को विद्यार्थियों में विकसित करना है। इस योजना के माध्यम से सन 2026–27 तक तीसरी कक्षा के अंत तक विद्यार्थियों में पढ़ने, लिखने एवं आधारभूत अंकगणित की क्षमता प्राप्त हो सकेगी। प्रस्तुत शोध हेतु उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से 87 परिषदीय विद्यालयों तथा उनमें अध्ययनरत कक्षा 1, 2 व 3 के 748 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक न्यादर्श विधि से किया गया है। प्रस्तुत शोध एक मात्रात्मक प्रवृत्ति का शोध है। आँकड़ों के संग्रह हेतु स्वनिर्मित 'निपुण दक्षता व विद्यालय सर्वेक्षण अनुसूची' का प्रयोग शोधकर्ता द्वारा किया गया है। आँकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रतिशतता सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है। आँकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि हिंदी भाषा में कक्षा 1, 2 व 3 में निपुणता प्रतिशत क्रमशः 61.29, 58.06 व 65.73 प्रतिशत पाया गया। गणित में कक्षा 1, 2 व 3 में निपुणता प्रतिशत क्रमशः 65.86, 58.46 व 64.94 प्रतिशत पाया गया। परिषदीय विद्यालयों

**शिक्षक-प्रशिक्षक*, नियोजन एवं प्रबंधन विभाग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बुढ़नपुर, अमरोहा, उत्तर प्रदेश 244 221
***सह-आचार्य*, बी.एड./एम.एड. विभाग, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश 243 006
****सह-आचार्य*, शिक्षा विभाग, राजकीय रजा पी.जी. कॉलेज, रामपुर, उत्तर प्रदेश 244 901

में निपुणता प्राप्त करने में कुछ प्रमुख चुनौतियाँ, जैसे— शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मियों की कमी, अभिभावकों का जागरूक न होना, चारदीवारी व स्वच्छ पेय जल का अभाव, शौचालय का साफ व स्वच्छ न होना, विद्यालयों में कम नामांकन, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग न होना, शिक्षकों की अकादमिक जवाबदेही न होना, नो डिटेंशन पॉलिसी, मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन, विद्युत उपलब्धता की कमी, खेल का मैदान व्यवस्थित न होना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का नियमित आयोजन न होना आदि परिलक्षित हुईं।

परंपरागत अर्थ में भारतीय उपनिषदों में शिक्षा के लिए— 'सा विद्या या विमुक्त्ये' कहा गया है, जिसका अर्थ है कि शिक्षा प्राणी को अंधकार से मुक्त करके प्रकाश की ओर लेकर जाती है।

महान भारतीय दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को मनुष्य में पूर्व से उपस्थित पूर्णता की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है। शिक्षा मानव के विकास हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला सबसे प्रभावी साधन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के समस्त पक्षों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। शिक्षा एक अखंड तत्व है। शिक्षा का वास्तविक व मूल कार्य मनुष्य का आंतरिक व चारित्रिक रूप से नव-निर्माण करना है, जो व्यक्ति, समाज एवं पर्यावरण तीनों का सामंजस्य कर मानव को सत्यम, शिवम और सुंदरम की ओर ले जा सके (अग्रवाल, सत्तार और जैन, 2020)।

भारतीय शिक्षा आयोग (1964–66) ने अपनी रिपोर्ट का शुभारंभ इन शब्दों के साथ किया— "भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है"। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के विकास एवं सुधार हेतु कई आयोगों एवं समितियों का गठन किया जा चुका है, जिनमें विभिन्न प्रकार से शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है तथा शिक्षा को मानवीय व्यवहार के विकास हेतु अनिवार्य बताया है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) का गठन किया गया, जिसने शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर सुझाव दिए तथा साथ ही साथ यह माना कि भारतीय शिक्षा का पाठ्यक्रम भारत की सांस्कृतिक विरासत, मानव मूल्यों, विश्व बंधुत्व तथा नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होना चाहिए, जिससे शिक्षा द्वारा एक उत्तम नागरिक का निर्माण किया जा सके। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) ने भी शिक्षा को मानवीय गुणों को विकसित करने एवं आदर्श नागरिक विकसित करने के रूप में देखा। कोठारी आयोग (1964–66) ने अपनी एक अनुशंसा में कहा था कि "शिक्षा किसी भी देश के विकास का सबसे शक्तिशाली साधन है जो सभी नागरिकों को अवसरों की समानता देकर उन्हें देश के भावी विकास हेतु तैयार करती है"। नई शिक्षा नीति 1986 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी शिक्षा को मानव के कल्याण हेतु एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे नागरिकों को व्यावहारिक व तकनीकी रूप से कुशल बनाकर राष्ट्र का विकास किया जा सके। भारतीय दर्शनों में कहा गया है कि जीव अज्ञान के कारण ही बार-बार

जन्म लेता और मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राचीन काल में शिक्षा मोक्ष के लिए आत्म ज्ञान का साधन थी तथा मोक्ष प्राप्ति में सहायक मानी जाती थी (राधा कुमुद मुकर्जी, 1951)।

विस्तृत अर्थ में शिक्षा मनुष्य की आयु से प्रतिबंधित नहीं है अर्थात जीवन की प्रत्येक अवस्था में सीखा जा सकता है। मनुष्य को नए-नए अनुभवों व परिवर्तित होती परिस्थितियों से सीखने की आवश्यकता सदैव ही रहती है, जिससे मनुष्य को भाँति-भाँति की परिस्थितियों में समायोजन करने में सहायता मिलती है। अतः जीवन में जागरूकता व उत्सुकता बनाए रखने के लिए जीवन पर्यंत सीखना आवश्यक है (जार्विस, 2004)। उत्तम नागरिक तैयार करने में शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि है, जो आदर्श व नैतिकता एक शिक्षक के व्यवहार में होते हैं उन्हीं आदर्शों व व्यवहार की छाया उसके विद्यार्थियों में आने की संभावना अधिक रहती है। अतः एक आदर्श शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में अपने व्यवहार को संतुलित बनाए रखें तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को भी सहभागी बनने के अवसर प्रदान करें, इससे विद्यार्थियों के मन में अपने शिक्षक के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न होती है तथा वे शिक्षक के व्यवहार को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। प्राचीन काल में शिक्षक प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थी के जीवन को प्रभावित करते थे तथा अपने विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का विकास करना अपना उद्देश्य समझते थे। गुरु-शिष्य के संबंध गरिमापूर्ण व अभिभावक समान होते थे। गुरु का स्थान विद्यार्थी के जीवन में सर्वोपरि व सर्वोत्तम होता था। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों के कर्तव्य के साथ ही साथ गुरु के कर्तव्य व उत्तरदायित्वों का भी वर्णन मिलता है। शिष्य के रहन-सहन, भरण-पोषण तथा योगक्षेम का समस्त भार गुरु पर ही होता था। आवश्यकता होने पर गुरु रुग्णावस्था में शिष्य की सेवा भी करते थे (चौबे और चौबे, 1959)।

प्राथमिक शिक्षा को विद्यार्थी जीवन का आधार माना जाता है, जो विद्यार्थी के शैक्षिक भविष्य को निर्धारित करती है। भारत में वैदिक काल से ही प्राथमिक शिक्षा की महत्ता पर बल दिया जाता रहा है। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा गुरुकुलों व आश्रमों में गुरु द्वारा प्रदान की जाती थी। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा, बौद्ध मठों में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रदान की जाती थी। मध्यकाल में भारत में मुस्लिम शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ जो मकतबों में मुस्लिम शिक्षकों द्वारा दी जाती थी। भारत में ब्रिटिश काल में परंपरागत भारतीय शिक्षा तंत्र छिन्न-भिन्न हो गया था तथा अंग्रेजी शिक्षा तंत्र का आगमन हुआ जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव डाली। स्वतंत्रता पश्चात भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता की ओर विशेष ध्यान दिया गया तथा अनेक शैक्षिक आयोग, समितियाँ, शिक्षा नीतियाँ एवं पाठ्यचर्याओं का निर्माण किया गया। शिक्षण सदैव से एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया रही है। शिक्षण मुख्य रूप से व्यक्ति की मनोवृत्ति, अभिरुचि व अंत:प्रेरणा से प्रेरित रहता है, जो शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यह न्यायसंगत एवं उचित ही है कि शिक्षण में निरंतर मनोवैज्ञानिक रीतियों व प्रविधियों का प्रचलन

बढ़ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा में मनोवैज्ञानिकरण, शैक्षिक गुणवत्ता व विद्यार्थी में कुशलताओं के विकास के विजन को लेकर तैयार की गई एक विस्तृत शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में आधारभूत गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन (NIPUN— National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding & Numeracy) का आरंभ 5 जुलाई 2021 को किया गया। निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को विद्यार्थियों में विकसित करना है। इस योजना के माध्यम से सन 2026–27 तक तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों में पढ़ने, लिखने एवं आधारभूत अंकगणित की क्षमता प्राप्त हो सकेगी। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एवं मूलभूत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस मिशन के उद्देश्य को 2026–27 तक प्राप्त किया जाएगा जिसके माध्यम से कक्षा 3 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को मूलभूत साक्षरता तथा संख्या ज्ञान प्रदान किया जाएगा। सभी जिला स्तर पर यह राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत 3–9 वर्ष तक की आयु के बच्चे शामिल किए जाएँगे। इस मिशन का संचालन समग्र शिक्षा के अंतर्गत किया जाएगा।

शोध समस्या

'परिषदीय विद्यालयों में निपुण भारत मिशन की कार्यान्वयन स्थिति एवं चुनौतियों का अध्ययन।'

शोध अध्ययन के उद्देश्य

1. परिषदीय विद्यालयों में निपुण भारत मिशन की कार्यान्वयन स्थिति का अध्ययन करना।
2. परिषदीय विद्यालयों में भाषा निपुणता की स्थिति का अध्ययन करना।
3. परिषदीय विद्यालयों में गणित निपुणता की स्थिति का अध्ययन करना।
4. परिषदीय विद्यालयों में निपुणता प्राप्त करने में आ रही चुनौतियों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु सर्वेक्षण अनुसंधान शोध विधि का प्रयोग किया गया है। आँकड़ों की दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन मात्रात्मक अनुसंधान है। मानविकी अनुसंधानों में, जहाँ मानवीय व्यवहार का मापन किया जाता है, वहाँ अनेकों बाहरी चर अनुसंधान व उसके परिणाम को प्रभावित करते हैं, इन्हीं कारणों के कारण अधिकांश मानविकी अनुसंधानों में सर्वेक्षण अनुसंधानों का प्रयोग किया जाता है।

शोध जनसंख्या

प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोध जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में संचालित परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1, 2 व 3 के विद्यार्थियों को जनसंख्या के रूप में माना गया है।

प्रस्तुत अध्ययन का सीमांकन जनपद अमरोहा के परिषदीय विद्यालयों तक किया गया है।

शोध न्यादर्श व विधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु सर्वप्रथम संपूर्ण जनसंख्या से जनपद के कुल 6 विकास खंडों से कुल 87 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया। इसके पश्चात उक्त 87 विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1, 2 व 3 के कुल 748 विद्यार्थियों का चयन साधारण यादृच्छिक विधि से अध्ययन हेतु निम्न प्रकार किया गया—

तालिका 1— अध्ययन हेतु शोध न्यादर्श का चयन

क्र.सं.	विकास खंड	चयनित विद्यालयों की संख्या	चयनित विद्यार्थियों की संख्या
1.	अमरोहा	13	110
2.	गजरौला	14	120
3.	धनौरा	16	138
4.	गंगेश्वरी	15	130
5.	जोया	13	110
6.	हसनपुर	16	140
कुल	**06**	**87**	**748**

शोध उपकरण

शोध उपकरण के रूप में स्व-निर्मित 'निपुण दक्षता व विद्यालय सर्वेक्षण अनुसूची' का निर्माण कक्षा 1, 2 व 3 के विद्यार्थियों की भाषायी व गणितीय निपुण दक्षता मापने हेतु किया गया है। निपुण दक्षता व विद्यालय सर्वेक्षण अनुसूची का निर्माण 2 भागों में किया गया है। उपकरण के पहले भाग में कक्षा 1, 2 व 3 के विद्यार्थियों की भाषायी व गणितीय निपुण दक्षता मापने हेतु पैमाना दिया गया है, जिसमें विद्यार्थियों की निपुण, अनिपुण व निपुणता प्रतिशत स्थिति को मापा गया है। प्रत्येक कक्षा से कुल 6 विद्यार्थियों का (3 भाषायी दक्षता हेतु व 3 गणितीय दक्षता हेतु) आकलन कर मापन पूर्ण किया गया है। उपकरण में निपुणता पैमाने को निम्नवत प्रदर्शित किया गया है—

कक्षा 1 के विद्यार्थियों हेतु भाषायी दक्षता की स्थिति—

I. विद्यार्थी 1— (क) निपुण (ख) अनिपुण (ग) निपुणता प्रतिशत

II. विद्यार्थी 2— (क) निपुण (ख) अनिपुण (ग) निपुणता प्रतिशत

III. विद्यार्थी 3— (क) निपुण (ख) अनिपुण (ग) निपुणता प्रतिशत

कक्षा 1 के विद्यार्थियों हेतु गणितीय दक्षता की स्थिति—

I. विद्यार्थी 1— (क) निपुण (ख) अनिपुण (ग) निपुणता प्रतिशत

II. विद्यार्थी 2— (क) निपुण (ख) अनिपुण (ग) निपुणता प्रतिशत

III. विद्यार्थी 3— (क) निपुण (ख) अनिपुण (ग) निपुणता प्रतिशत

उपकरण के दूसरे भाग में विद्यालय का सर्वेक्षण कर सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु 'हाँ' और 'नहीं' विकल्पों के साथ प्रश्नों/कथनों को रखा गया है।

संपूर्ण शोध उपकरण में कुल 60 प्रश्न रखे गए हैं। उपकरण के प्रथम भाग में 1 विमा को रखा गया है, जबकि द्वितीय भाग में 8 विमाओं को रखा गया है।

उपकरण के प्रथम व द्वितीय भागों में प्रश्नों की संख्या निम्नवत रखी गई है—

तालिका 2— निपुण दक्षता व विद्यालय सर्वेक्षण अनुसूची हेतु विमाएँ व प्रश्न

क्र.सं.	विमाएँ	उपकरण में क्र. संख्या	कथनों की संख्या
1.	निपुण दक्षता आकलन	1–6	06
2.	भौतिक व मानवीय संसाधन	7–12	06
3.	मिशन कायाकल्प	13–13	01
4.	विद्यालय प्रबंधन	14–16	03
5.	प्रिंट रिच कक्षाएँ व शिक्षण अधिगम सामग्री	17–23	07
6.	शिक्षण–अधिगम प्रविधि	24–30	07
7.	सामुदायिक सहभागिता एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएँ	31–38	08
8.	शैक्षिक प्रशासन एवं नीतियाँ	39–47	09
9.	नवाचारिक गतिविधियाँ	48–53	06
10.	शिक्षक स्व-मूल्याँकन	54–60	07
कुल			**60**

उपकरण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के परीक्षण–पुनः परीक्षण विधि का प्रयोग किया गया। इस विधि में परीक्षण को न्यादर्श पर प्रशासित किया जाता है तथा प्राप्तांक प्राप्त कर लिए जाते हैं। उसी परीक्षण को लगभग 14 दिनों के अंतराल में पुनः उसी न्यादर्श पर प्रशासित किया जाता है तथा प्राप्तांकों की गणना कर ली जाती है। इस प्रकार एक ही परीक्षण के दो प्राप्तांक सेट प्राप्त हो जाते हैं। बाद में प्राप्तांकों के इन दोनों वितरणों में सह-संबंध ज्ञात किया जाता है। यही परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक कहलाता है तथा इसे तकनीकी अर्थ में कालिक स्थिरता गुणांक कहा जाता है। इससे यह पता लगता है कि एक दिए हुए परीक्षण पर प्राप्तांक कितना स्थिर है या कितना संगत है। यही सह-संबंध गुणांक या स्थिरता गुणांक परीक्षण की विश्वसनीयता कहलाता है। उक्त शोध उपकरण की विश्वसनीयता भी परीक्षण–पुनः परीक्षण विधि द्वारा ज्ञात की गई जो 0.84 प्राप्त हुई। उपकरण की वैद्यता ज्ञात करने हेतु उपकरण को 3 विषय विशेषज्ञों को दिया गया तथा उनकी अनुसंशा के आधार पर उपकरण की रूप वैद्यता व विषयगत वैद्यता संतोषजनक निर्धारित की गई।

सांख्यिकी प्रविधि

प्रस्तुत शोध आँकड़ों का विश्लेषण करने हेतु प्रतिशतता सांख्यिकी का प्रयोग किया गया।

आँकड़ो का विश्लेषण

1. निपुण दक्षता आकलन

आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिए एकत्रित आँकड़ों की प्रतिशतता ज्ञात की गई। शोध उद्देश्यों के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1, 2 व 3 के विद्यार्थियों के मध्य हिंदी भाषा व गणित निपुणता प्रतिशत निम्नवत ज्ञात किया गया है—

- **परिषदीय विद्यालयों में भाषा निपुणता आकलन की स्थिति**— निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति के आकलन हेतु आँकड़ों का संकलन कक्षावार किया गया है। जिसका विश्लेषण कक्षा एवं विषयवार निम्न प्रकार है—

  परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 में कुल 249, कक्षा 2 में कुल 248 तथा कक्षा 3 में कुल 251 विद्यार्थियों

का हिंदी भाषा निपुण दक्षता परीक्षण किया गया। निपुण दक्षता परीक्षण से ज्ञात हुआ कि कक्षा 1 के 61.29 प्रतिशत विद्यार्थी, कक्षा 2 के 58.06 प्रतिशत विद्यार्थी तथा कक्षा 3 के 65.73 प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी भाषा में निपुण पाए गए।

तालिका 3— कक्षावार हिंदी भाषा निपुणता प्रतिशत

कक्षा	कुल आकलित विद्यार्थी	निपुण विद्यार्थी	निपुणता प्रतिशत
1.	249	152	61.29
2.	248	144	58.06
3.	251	165	65.73

रेखाचित्र 1— कक्षावार हिंदी भाषा निपुणता प्रतिशत

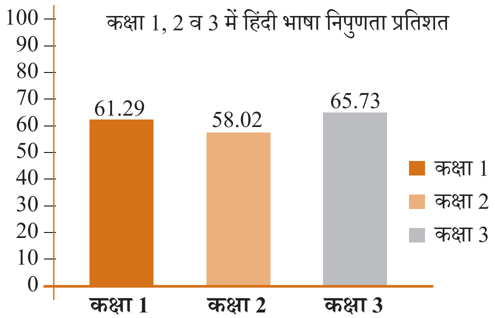

कक्षा 1 हिंदी भाषा में बालकों का निपुणता प्रतिशत 61.29, जबकि बालिकाओं का निपुणता प्रतिशत 45.70 ज्ञात हुआ। कक्षा 2 के बालकों का निपुणता प्रतिशत 55, जबकि बालिकाओं का निपुणता प्रतिशत 45 ज्ञात हुआ। कक्षा 3 के बालकों का निपुणता प्रतिशत 53.60, जबकि बालिकाओं का निपुणता प्रतिशत 46.40 ज्ञात हुआ।

रेखाचित्र 2— बालक-बालिका निपुणता प्रतिशत

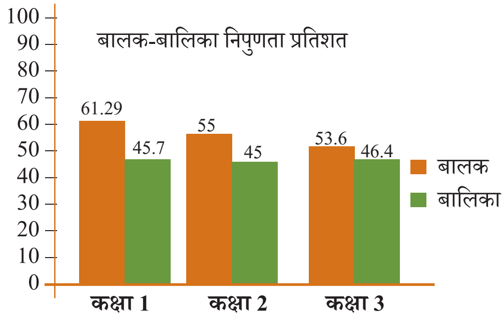

बालकों के सापेक्ष बालिकाओं का निपुणता प्रतिशत कम रहने के अनेक कारण परिलक्षित हुए, जैसे— बालिकाओं की विद्यालय में कम उपस्थिति, बालिकाओं का घरेलू कार्यों व अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल में व्यस्त रहना, बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिभावकों का कम जागरूक होना आदि।

- **परिषदीय विद्यालयों में गणित निपुणता आकलन की स्थिति**— निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति के आकलन हेतु आँकड़ों का संकलन कक्षावार किया गया है, जिसका विश्लेषण कक्षा एवं विषयवार निम्न प्रकार है—

  परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 में कुल 249, कक्षा 2 में कुल 248 तथा कक्षा 3 में कुल 251 विद्यार्थियों का गणित निपुण दक्षता परीक्षण किया गया। निपुण दक्षता परीक्षण से ज्ञात हुआ कि कक्षा 1 के 65.86 प्रतिशत विद्यार्थी, कक्षा 2 के 58.46 प्रतिशत विद्यार्थी तथा कक्षा 3 के 64.94 प्रतिशत विद्यार्थी गणित में निपुण पाए गए।

तालिका 4— कक्षावार गणित निपुणता प्रतिशत

कक्षा	कुल आकलित विद्यार्थी	निपुण विद्यार्थी	निपुणता प्रतिशत
1.	249	164	65.86
2.	248	145	58.46
3.	251	163	64.94

रेखाचित्र 3— कक्षावार गणित निपुणता प्रतिशत

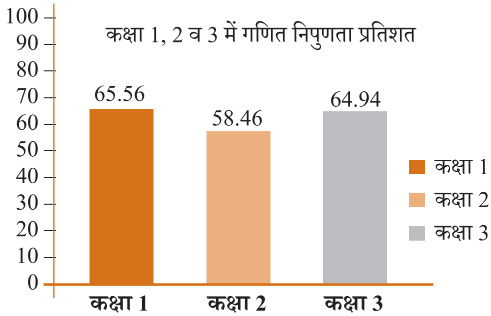

कक्षा 1 में बालकों का गणित में निपुणता प्रतिशत 55, जबकि बालिकाओं का निपुणता प्रतिशत 45 प्राप्त हुआ। कक्षा 2 में बालकों का गणित निपुणता प्रतिशत 56.20, जबकि बालिकाओं का निपुणता प्रतिशत 43.80 प्राप्त हुआ। कक्षा 3 में बालकों का गणित निपुणता प्रतिशत 58.15, जबकि बालिकाओं का गणित निपुणता प्रतिशत 41.85 पाया गया।

रेखाचित्र 4— बालक-बालिका गणित निपुणता प्रतिशत

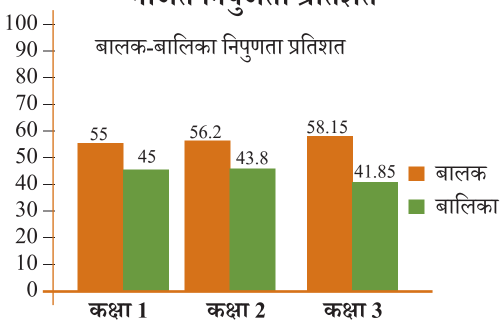

बालकों के सापेक्ष बालिकाओं का निपुणता प्रतिशत कम रहने के अनेक कारण परिलक्षित हुए, जैसे— बालिकाओं की विद्यालय में कम उपस्थिति, बालिकाओं का घरेलू कार्यों व अपने छोटे भाई- बहनों की देखभाल में व्यस्त रहना, बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिभावकों का कम जागरूक होना आदि।

उपरोक्त परिणामों से स्पष्ट है कि ग्रामीण विद्यालयों में बालिकाओं का निपुणता प्रतिशत बालकों से कम पाया गया। इसी संदर्भ में दास एवं सिंघल (2022) ने 2010 से 2018 तक के 'असर' रिपोर्ट के आँकड़ों के आधार पर बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की गणितीय कुशलता बालकों की अपेक्षा कम रही है, जबकि किंग एवं गुरुयन (2006) द्वारा अपने शोध अध्ययन 'टीचिंग टू द माइंड्स ऑफ बॉयस' में बताया कि कोलोराडो स्टेट असेसमेंट प्रोग्राम (सी.एस.ए.पी.) में बालिकाओं द्वारा बालकों की अपेक्षा 13 पॉइंट अधिक परिणाम प्राप्त किया गया। बालिकाओं की अधिक अधिगम निष्पत्ति का कारण विद्यालयी कक्षाओं का बालिकाओं के अनुकूल होना बताया गया। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यदि बालिकाओं को भी अध्ययन के समान अवसर दिए जाएँ तो वे भी बालकों के समान अधिगम उपलब्धि प्राप्त कर सकती हैं। भारतीय ग्रामीण परिवेश में अभी भी बालिकाओं को शिक्षा का समान अवसर नहीं मिल पा रहा है।

2. भौतिक व मानवीय संसाधनों की उपलब्धता

निपुण भारत मिशन व शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु आवश्यकतानुसार भौतिक व मानवीय

संसाधनों की उपलब्धता पर बल देते हैं। निपुणता प्राप्त करने हेतु विद्यालय में आवश्यक भौतिक व मानवीय संसाधन आवश्यक हैं। तालिका संख्या 5 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में भौतिक व मानवीय संसाधनों की उपलब्धता का प्रतिशत प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 5— भौतिक व मानवीय संसाधनों की उपलब्धता का प्रतिशत

क्र.सं.	कथन	उपलब्धता का प्रतिशत
1.	क्या विद्यालय में चारदीवारी है?	92.00
2.	क्या विद्यालय में व्यवस्थित खेल का मैदान है?	73.00
3.	क्या विद्यालय भवन पर्याप्त व सही स्थिति में है?	77.77
4.	क्या प्रत्येक कक्षा के लिए अलग-अलग कक्ष उपलब्ध हैं?	40.03
5.	क्या विद्यालय में पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक नियुक्त है?	63.96
6.	क्या विशिष्ट बच्चों हेतु विशिष्ट शिक्षक की सेवाएँ उपलब्ध हैं?	04.76

3. मिशन कायाकल्प

सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु मिशन कायाकल्प का शुभारंभ किया गया है। वर्तमान में कुल 19 पैरामीटर के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को संतृप्त किए जाने का कार्य किया जा रहा है। पैरामीटर की वर्तमान उपलब्धता तालिका 6 में प्रदर्शित की गई है।

तालिका 6— मिशन कायाकल्प पैरामीटर की उपलब्धता प्रतिशत

क्र.सं.	कथन/पैरामीटर	उपलब्धता का प्रतिशत
1.	सुरक्षित व शुद्ध पेयजल	96.82
2.	सबमर्सिबिल जल आपूर्ति	93.65
3.	कार्यशील बालक शौचालय	90.47
4.	कार्यशील बालिका शौचालय	90.47
5.	कार्यशील बालक यूराइनल	60.31
6.	कार्यशील बालिका यूराइनल	58.73
7.	शौचालय में जल की उपलब्धता	87.30
8.	शौचालय में टाइल्स	92.00
9.	दिव्यांग शौचालय	66.66
10.	हैंड वाश यूनिट	77.77
11.	कक्षाओं में फर्श का टाइलीकरण	63.49
12.	ब्लैक/व्हाइट बोर्ड	87.30
13.	विद्यार्थियों हेतु डेस्क बैंच	34.92
14.	रसोई घर की उपलब्धता	92.06
15.	विद्यालय की पुताई एवं पेंटिंग	77.77
16.	रेलिंग सहित रैम्प	92.00
17.	नियमानुसार विद्युतीकरण	100.0
18.	विद्यालय विकास योजना का निर्माण	23.80
19.	विद्यालय का विद्युत कनेक्शन	96.82

4. विद्यालय प्रबंधन

शैक्षिक गुणवत्ता व विद्यालय संचालन हेतु विद्यालय प्रबंधन एक आवश्यक तत्व है। उत्तम विद्यालय प्रबंधन ही उत्तम शैक्षिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। परिषदीय विद्यालयों में प्रबंधन के कुछ आयामों की प्रतिशतता को तालिका 7 में दर्शाया गया है।

तालिका 7— विद्यालय प्रबंधन की स्थिति

क्र.सं.	कथन	प्रतिशत
1.	क्या विद्यालय में कक्षाओं का संचालन समय-सारणी के अनुसार हो रहा है?	47.61
2.	क्या विद्यालय परिसर व कक्षाएँ साफ-सुथरी हैं?	90.47
3.	क्या विद्यालय के सभी बच्चे स्कूल गणवेश (यूनिफोर्म) में हैं?	25.39

5. प्रिंट रिच कक्षा व शिक्षण सामग्री

शिक्षण को सरल, ग्राह्य व स्थायी बनाने हेतु यह आवश्यक है कि विद्यालय के वातावरण व कक्षाओं को अधिक से अधिक प्रिंट रिच बनाया जाए। शिक्षण हेतु विद्यालय में आवश्यक शिक्षण सामग्री का उपलब्ध होना भी आवश्यक है। परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध प्रिंट रिच कक्षा व शिक्षण सामग्री की उपलब्धता को तालिका 8 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 8— प्रिंट रिच कक्षा व शिक्षण सामग्री की प्रतिशतता

क्र.सं.	कथन	प्रतिशत
1.	क्या कक्षाओं को प्रिंट रिच बनाया गया है?	68.25
2.	क्या विद्यार्थी कक्षा मे लगी प्रिंट रिच सामग्री के बारें में जागरूक हैं?	57.14
3.	क्या प्रत्येक कक्षा में कार्यशील रीडिंग कोर्नर निर्मित है?	46.03
4.	क्या कक्षाओं में शिक्षण के समय 15 कहानी – कविता चार्ट्स का उपयोग किया जा रहा है?	65.07
5.	क्या विद्यालय में 5 बिग बुक उपलब्ध हैं?	93.65
6.	क्या विद्यालय में 2 गणित किट उपलब्ध हैं?	100.00
7.	क्या शिक्षक, शिक्षण में शिक्षण-अधिगम सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं?	73.01

6. शिक्षण अधिगम प्रविधि

शिक्षण अधिगम प्रविधि कक्षा में समावेशन लाने व प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षित करने हेतु आवश्यक है। शिक्षण अधिगम प्रविधि शिक्षण को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। तालिका 9 में शिक्षण अधिगम प्रविधि की क्रियाओं की प्रतिशतता को दर्शाया गया है।

तालिका 9— शिक्षण अधिगम प्रविधि की स्थिति व प्रतिभागिता

क्र.सं.	कथन	प्रतिशत
1.	क्या कक्षा शिक्षण गतिविधि आधारित है?	63.31
2.	क्या कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की सहभागिता है?	65.07
3.	क्या शिक्षक स्व-निर्मित शिक्षण योजना के अनुसार शिक्षण कार्य कर रहें हैं?	22.22
4.	क्या शिक्षण कार्य शिक्षक संदर्शिका के अनुसार हो रहा है?	80.92
5.	क्या शिक्षक अपनी शिक्षक डायरी नियमित पूर्ण करते हैं?	53.96
6.	क्या विद्यालय में सुसज्जित व कार्यशील पुस्तकालय है?	63.49
7.	क्या मंद गति से सीखने वाले बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण दिया जा रहा है?	81.74

7. सामुदायिक सहभागिता एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएँ

ग्रामीण परिवेश के विद्यालयों को समुदाय से जोड़ना आवश्यक है। इसलिए परिषदीय विद्यालयों में अनेक प्रकार की सामुदायिक बैठकें व कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ शिक्षा को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ने हेतु विद्यालयों में अनेक पाठ्य-सहगामी क्रियाएँ कराए जाने का प्रावधान किया गया है। परिषदीय विद्यालयों में सामुदायिक

सहभागिता एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएँ कराए जाने की स्थिति तालिका 10 में दर्शाई गई है।

तालिका 10— सामुदायिक सहभागिता एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं की प्रतिशतता

क्र.सं.	कथन	प्रतिशत
1.	क्या प्रतिमाह एजेंडे के अनुसार एस.एम.सी. की बैठक आयोजित की जा रही है?	50.79
2.	क्या एस.एम.सी. बैठक में सभी सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है?	60.30
3.	क्या नियमित रूप से शिक्षक-अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाता है?	80.95
4.	क्या शिक्षक-अभिभावक बैठक में सभी अभिभावकों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है?	30.20
5.	क्या नामांकन व उपस्थिति बढ़ाने हेतु समुदाय द्वारा सहयोग किया जाता है?	49.20
6.	क्या विद्यालय में नियमित रूप से प्रार्थना सभा व विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं?	84.12
7.	क्या विद्यार्थियों को खेलने के अवसर दिए जाते हैं?	90.47
8.	क्या विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाएँ आयोजित की जाती हैं?	42.85

8. शैक्षिक प्रशासन एवं नीतियाँ

परिषदीय विद्यालयों को दिशा व मार्गदर्शन देने हेतु अनेक शैक्षिक प्रशासन संबंधी नीतियाँ प्रचलन में है जिनके वर्तमान क्रियान्वयन की स्थिति तालिका 11 में प्रदर्शित की गई है।

तालिका 11— शैक्षिक प्रशासन एवं नीतियों के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र.सं.	कथन	प्रतिशत
1.	क्या किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण न करने से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी है?	6.34
2.	क्या शिक्षण में तकनीकी की निरंतर बढ़ती भूमिका से आप सहज अनुभव करते हैं?	88.88
3.	क्या शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी की बढ़ती भूमिका को आप आवश्यक मानते हैं?	96.82
4.	क्या विभाग द्वारा आपको प्रदान किए जा रहे सेवारत प्रशिक्षण शिक्षण हेतु लाभदायक है?	98.41
5.	क्या ऑनलाइन प्रशिक्षण, ऑफलाइन प्रशिक्षण से अधिक लाभदायी हैं?	19.04
6.	क्या आप विभाग द्वारा प्रेषित शिक्षण अधिगम सामग्री को समझकर कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर पा रहे हैं?	92.06
7.	क्या मिड-डे मील योजना से शिक्षक के शिक्षण समय की हानि हो रही है?	82.53
8.	क्या मिड-डे मील योजना से विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ रही है?	71.42
9.	क्या मिड-डे मील विद्यार्थियों के पोषण हेतु आवश्यक है?	90.47

9. नवाचारिक गतिविधियाँ

किसी भी तंत्र को नवीनता व प्रगतिशीलता प्रदान करने हेतु नवाचार आवश्यक है। शैक्षिक प्रक्रिया में भी नवाचार व नवाचारिक गतिविधियाँ शिक्षा की ग्रहणशीलता, रुचि व ज्ञान के सरलीकरण हेतु आवश्यक हैं। तालिका 12 में नवाचारिक गतिविधियों की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 12— नवाचारिक गतिविधियों की कार्यान्वयन स्थिति व प्रतिशतता

क्र.सं.	कथन	प्रतिशत
1.	क्या आपने कोई शैक्षिक नवाचार किया है?	01.58

2.	क्या आप कक्षा में कोई नवाचारिक गतिविधि कराते हैं?	39.68
3.	क्या आपका शिक्षण दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित है?	93.65
4.	क्या विद्यालय में शिक्षक-विद्यार्थियों के मध्य आत्मिक संबंध स्थापित करने हेतु गतिविधियाँ की जा रही हैं?	95.23
5.	क्या गत दो वर्षों में आपने शिक्षण की कोई नवीन पद्धति सीखी है?	76.19
6.	क्या विद्यालयों की मेंटरिंग से विद्यालय विकास में सहायता मिल रही है?	100.00

10. शिक्षक स्व-मूल्यांकन

अपने कार्यों का सच्चा पर्यवेक्षक एवं विश्लेषणकर्ता व्यक्ति स्वयं होता है। स्व-मूल्यांकन अपने कार्यों व उत्तरदायित्वों के प्रति एक भावना है जो व्यक्ति को अपना दायित्व निभाने हेतु प्रेरित करती है। तालिका 13 में शिक्षक स्व-मूल्यांकन की स्थिति प्रदर्शित की गई है।

तालिका 13— शिक्षक स्व-मूल्यांकन का प्रतिशत

क्र.सं.	कथन	प्रतिशत
1.	क्या आपको लगता है कि आपके विद्यालय में टीम भावना के साथ कार्य किया जा रहा है?	68.25
2.	क्या विभाग द्वारा प्रदान किए जा रहे सेवारत प्रशिक्षण आपके लिए लाभदायक हैं?	98.41
3.	क्या आपको लगता है कि आप विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति हेतु अभिभावकों को सहमत कर पा रहे हैं?	61.90
4.	क्या आपको लगता है कि आपका शिक्षण उत्तम है?	92.06
5.	क्या आप अपने अनुसार विद्यालय में सुधार कर पा रहे हैं?	73.01
6.	क्या आपको लगता है कि आप पूर्ण निष्ठा से अपने उत्तरदायित्व को निभा पा रहे हैं?	96.82
7.	क्या आप अध्यापन हेतु अध्ययन को आवश्यक मानते हैं?	100.00

शोध परिणाम एवं परिचर्चा

तालिका 5–13 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्यालय को निपुण बनाने हेतु परिषदीय विद्यालयों में कुछ संसाधनों की उपलब्धता व गुणवत्ता अच्छी स्थिति में है, कुछ संसाधनों की उपलब्धता व गुणवत्ता मध्यम स्थिति में है, जबकि कुछ संसाधनों की उपलब्धता व गुणवत्ता बहुत दोयम व निराशाजनक स्थिति में है, जिसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है। परिषदीय विद्यालयों में कुछ संसाधन व गतिविधियाँ, जैसे— विद्यालय में चारदीवारी की उपलब्धता, सुरक्षित व शुद्ध पेय जल की उपलब्धता, सबमर्सिबल द्वारा जल आपूर्ति, कार्यशील बालक-बालिका शौचालय, शौचालय में टाइलें, व्हाइट एवं ब्लैक बोर्ड की उपलब्धता, रसोईघर की उपलब्धता, रेलिंग व रैम्प की उपलब्धता, नियमानुसार विद्युत कनेक्शन, विद्यालय में बिग बुक की उपलब्धता, विद्यार्थियों को खेलने के अवसर देना, शिक्षकों द्वारा तकनीकी सहजता, सेवारत प्रशिक्षणों की लाभदायकता, शिक्षकों द्वारा शिक्षण-अधिगम सामग्री को समझना, मिड-डे मील को विद्यार्थियों के पोषण हेतु आवश्यक मानना, शिक्षण का दैनिक अनुभवों पर आधारित होना, शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य आत्मिक संबंध होना, मेंटरिंग से विद्यालय विकास में सहायता मिलना, सेवारत प्रशिक्षणों

की लाभदायकता, शिक्षक द्वारा उत्तम शिक्षण की स्वीकार्यता, शिक्षक द्वारा मानना कि वे निष्ठापूर्वक अपना उत्तरदायित्व निभा पा रहे हैं, शिक्षक द्वारा अध्यापन हेतु अध्ययन को आवश्यक मानना आदि की स्थिति उत्तम पाई गई। प्रस्तुत शोध अध्ययन में कुछ संसाधनों व गतिविधियों, जैसे— व्यवस्थित खेल के मैदान की उपलब्धता, विद्यालय भवन की स्थिति व पर्याप्तता, पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति, बालक-बालिका शौचालय की उपलब्धता, शौचालय में जल की उपलब्धता, दिव्यांग शौचालय, हैंड वाश यूनिट व फर्श के टाइलीकरण की उपलब्धता, विद्यालय की पुताई व पेंटिंग, प्रिंट रिच कक्षा व विद्यार्थियों में प्रिंट रिच जागरूकता, शिक्षण में कहानी-कविता चार्ट का प्रयोग, शिक्षण में टीचिंग लर्निंग मटेरियल (टी.एल.एम.) का प्रयोग, गतिविधि आधारित शिक्षण-अधिगम, कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की सहभागिता, शिक्षक संदर्शिका के अनुसार शिक्षण कार्य, सुसज्जित पुस्तकालय की उपलब्धता, उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना, एजेंडे के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति बैठक आयोजन, शिक्षक-अभिभावक बैठक का नियमित आयोजन, एम.डी.एम. से विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण की नवीन पद्धति सीखना, टीम भावना के अनुसार कार्य करना आदि की स्थिति औसत पाई गई जिनमें और अधिक सुधार किए जाने की आवश्यकता है। जबकि कुछ संसाधनों व गतिविधियों, जैसे— प्रत्येक कक्षा हेतु अलग-अलग कक्षों की उपलब्धता, विशिष्ट शिक्षक की उपलब्धता, विद्यार्थियों हेतु डेस्क व बैंच की उपलब्धता, विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया जाना, समय-सारणी के अनुसार कक्षा संचालन न होना, विद्यार्थियों का विद्यालय यूनिफोर्म में होना, प्रत्येक कक्षा में कार्यशील रीडिंग कॉर्नर, स्व-निर्मित शिक्षण योजना के अनुसार शिक्षण कार्य, शिक्षक-अभिभावक बैठक में सभी अभिभावकों द्वारा प्रतिभाग, नामांकन व उपस्थिति बढ़ाने में समुदाय का सहयोग, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण नीति, ऑनलाइन प्रशिक्षण की लाभदायकता, शिक्षकों द्वारा शैक्षिक नवाचार किया जाना, कक्षा में नवाचारिक गतिविधि कराना आदि की स्थिति अत्यंत निराशाजनक पाई गई, जिसमें उत्तम शिक्षण-अधिगम हेतु तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

भारत तथा वैश्विक परिदृश्य पर अनेक शैक्षिक अध्ययनों के माध्यम से यह सिद्ध हो चुका है कि भौतिक व मानवीय संसाधनों की उपलब्धता शैक्षिक गुणवत्ता को प्रभावित करती है। अग्रवाल और पठानी (2021) ने अपने शोध अध्ययन में पाया कि उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालय प्रायः संरचनागत सुविधाओं व स्रोतों की कमी, जैसे— छोटे कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शिक्षकों की कमी, नवाचारिक शिक्षण, धीमी लर्निंग आउटकम, प्रयोगात्मक कुशलताओं की कमी से जूझ रहे हैं जिनके कारण शिक्षण की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जाटवा (2020) ने पाया कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सुनिश्चित शैक्षिक ढाँचे का अभाव है जिसका विपरीत प्रभाव नामांकन व शिक्षण की गुणवत्ता पर पड़ता है। बोरूह (2017) ने भी अपने शोध अध्ययन में बताया

कि प्राथमिक विद्यालयों में कुछ भौतिक व शैक्षिक सुविधाओं, जैसे— चारदीवारी की स्थिति, हेड मास्टर रूम, विद्यार्थी कॉमन रूम, खेल का मैदान, आवश्यक कक्षा-कक्ष आदि आंशिक रूप से ही उपलब्ध हैं जिससे परिणामस्वरूप विद्यार्थियों के अवधिपूर्व विद्यालय छोड़ने की दर अधिक है। अफेवर्क एवं असफा (2014) ने अपने शोध परिणामों में बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी का शिक्षण की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

उक्त अध्ययनों एवं शोध परिणामों से स्पष्ट है कि निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 1–3 तक विद्यार्थियों द्वारा गणित व भाषा में जो निपुणता प्राप्त की जानी है, उसके लिए आधारभूत भौतिक व मानवीय संसाधनों का विद्यालयों में उपलब्ध होना आवश्यक है। निस्संदेह विद्यालय का वातावरण व सुविधाएँ अच्छी व उन्नत होनी चाहिए, जिससे बालक पूरे विद्यालय समय में विद्यालय में ठहर सके। बालक के सीखने हेतु कुछ आधारभूत सुविधाएँ, जैसे— स्वच्छ शौचालय व पीने का पानी, पर्याप्त कक्षा-कक्ष व खेल का मैदान, सुरक्षित व ऊँची चारदीवारी, पर्याप्त शिक्षण व शिक्षणेत्तर कर्मचारी, सुंदर कक्षा-कक्ष व विद्यालयी परिवेश, प्रतिकूल मौसम से बचने हेतु सुविधाएँ, प्रशिक्षित शिक्षक, शिक्षण सहाय सामग्री आदि की महत्वपूर्ण भूमिका है। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य न केवल बालक की वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं को विकसित करना है, बल्कि भविष्य में विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए योग्य नागरिक भी तैयार करना है।

संदर्भ

अग्रवाल, ए.एस. और आर.एस. पठानी. 2021. ए कंपेरेटिव स्टडी ऑफ गवरमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स इन उत्तर प्रदेश. *आई.ओ.एस.आर. जर्नल ऑफ रिसर्च एंड मेथड इन एजुकेशन.* 11(1), पृ.सं. 52–55. 12 जुलाई 2024 को https://www.iosrjournals.org/iosr-jrme/papers/Vol-11%20Issue-1/Ser-7/I1101075255.pdf से प्राप्त।

अग्रवाल, एन., ए. सत्तार और जैन. 2020. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में संस्थागत वातावरण का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांसेस इन सोशल साइंसेस.* 8(3), पृ.सं. 69–77.

अफेवर्क, टी.एच. और एम.बी. असफा. 2014. द अवेलेबिलिटीस ऑफ स्कूल फेसिलिटीस एंड देयर इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गर्वमेंट प्राइमरी स्कूल्स ऑफ हरारी रीजनल स्टेट ईस्ट हरारे जोन, इथोपिया. *मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च.* 11, पृ.सं. 59–71. 12 जुलाई 2024 को https://arastirmax.com/tr/system/files/ dergiler/79204/makaleler/11/1/arastirmax-availability-school-facilities-and-their-effects-quality-education-government-primary-schools-harari-regional-state-and-east-hararghe-zone-ethiopia.pdf से प्राप्त।

किंग, के. और एम. गुरियन. 2006. टीचिंग टू द माइंड्स ऑफ बोयस. *एजुकेशनल लीडरशिप.* 64(1), पृ.सं. 56–58.

चौबे, एस.पी. और ए. चौबे. 1959. *एजुकेशन इन एन्सिएंट एंड मेडिएवल इंडिया*. विकास पब्लिशिंग हाउस, नोएडा

जाटवा, ए. 2020. स्टेट्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थोट्स,* 8(10), पृ.सं. 89–94.

जार्विस, पी. 2004. *एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग : थियरी एंड प्रेक्टिस*. रोटलेज फामर, लंदन

दास, यू और के. सिंघल. 2022. *जेंडर डिफेरेंसेस इन मेथमेटिक्स लर्निंग इन रूरल इडिंया*. आइडियास फॉर इंडिया (ऑनलाइन आर्टिकल). 17 जुलाई 2024 को https://www.ideasforindia.in/topics/human-development/gender-difference-in-mathematics-learning-in-rural-india.html से प्राप्त।

बोरूह, पी.जे. 2017. ए स्टडी ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फेसिलिटीस फॉर द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल्स विद स्पेशल रिफेरेंस टू नाजिरा सब-डिवीजन ऑफ शिब नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग डवलपमेंट एंड रिसर्च,* 5(4), पृ.सं. 960–963.

भारतीय शिक्षा आयोग रिपोर्ट 1964–66. शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली.

माध्यमिक शिक्षा आयोग रिपोर्ट 1952–53. शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली.

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986*. मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

मुकर्जी, आर.के. 1951. *एन्सिएंट इंडियन एजुकेशन : ब्राहमिनिकल एंड बुद्धिस्ट*. मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय. 1948–49. *विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग रिपोर्ट*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

———. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

———. 2021. *निपुण भारत मिशन 2021*. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.